

ग्रसाधारम्

EXTRAORDINARY

भाग I—शाष्ट्र 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 4]

नई बिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 3, 1974/पीष 13, 1895

No. 4]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 3, 1974/PAUSA 13, 1895

इस भाग में भिरम परुठ मंद्या दी जाती है जिसमें कि यह ग्रस्म संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICES

EMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 3rd January 1974

Subject.—Export of Natural Rubber

No. 1-ETC(PN)/74.—With immediate effect, Natural Rubber has been brought under Control $vide\ E(C)O,\ 1968/AM(115)$ of todate,

2. It has been decided to canalise the export of Natural Rubber through the State Trading Corporation of India, Ltd., New Delhi.

वाणिज्य पंत्राह्मय

सार्वजनिक सूचनाएं

नियति ब्यापार नियंक्षण

नई दिल्ती, 3 जनवरी, 1974

विषय.-प्राकृतिक रबड का निर्यात ।

सं० 1-ई० टी० जी० (पी०एस०)/74. --प्राकृतिक रवड़ की तत्काल नियंवण में ले लिया गया है। देखिए भ्राज का निर्यात (नियंवण) ग्रावेश, 1968/ए एस० /(115)।

- 2. प्राकृतिक रवड को राज्य ज्यापार निगम, भारत लि०, नई दिल्ली के माध्यम से सरणीबद्ध करने का निश्चय किया गया है।
- Subject.—Scheme for the licensing of Indian millmade cotton textiles including garments and mude-ups for export to DEN MARK AND IRELAND (IRISH REPUBLIC) during the licensing year 1974.
- No. 2-ETC(PN)/74.—The Scheme relates to the export of all varieties of mill-made cotton fabrics, made-up items and readymade garments made out of mill-made fabrics from India to DENMARK AND IRELAND during the licensing year, (st January, 1974 to 31st December, 1974.
- 2. For purpose of licensing the shipment period will be divided into two stx-monthly periods, 1st January, 1974 to 30th June. 1974 and 1st July. 1974 to 31st December, 1974.
- 3. Licences under the Scheme shall be issued by the Office of the Jt. Chief Controller of Imports & Exports, Bombay, on the basis of quota certificate issued by the Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay, on the recommendations of the EEC-Austria Textles Licensing Advisory Committee.
- 4. For the purpose of exports and issuance of quotas/licences,, cotton textiles have been divided into the following two groups:—
 - Group I:-Cotton fabrics, grey or bleached mercerised or not:

Grown I covers items classified under categories B, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, C and C1.

Group II:—Other cotton fabrics, made-up articles and miscellaneous articles of cotton:

Group II covers items falling under categories C2, C3, C4, C5, C6, C7, D. D1, D2, D3, D4, E, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, F, F1, F2, F3 and F4.

Details of the items falling under the above categories are available with the Texprocil in the form of standardised categories and items falling under the same.

- 5. According to the agreement, imports of cotton textiles into Denmark and Ireland will be admitted by the respective competent Authorities only on presentation of the Green Certificates issued by the Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay, on the basis of which Denish and Irish Authorities would issue import licence.
 - 6. Licences shall be valid for shipment from any port in India.
- 7. Licences and quotas shall not be transferable without the express consentation writing of the E.E.C. and Austria Textiles Licensing Advisory Committee.
- 8. A non-refundable charge of Rs. 10/- per ton will be levied by The Cotton Textiles Export Promotion Council for the issue of quotas, subject to a minimum of Rs. 5/-.
- 9. All quota holders shall have to submit a monthly report to The Cotton Textiles Export Promotion Council, giving details of the shipment against individual licences issued to them. These statements should reach the Council by the 10th of the subsequent month.
- 10. The E.E.C.-Austria Textiles Licensing Advisory Committee shall (a) supervise the entire scheme: (b) keep a watch over the performance from time to time; (c) interpret and give decisions on various matters arising out of the operation of the scheme; and (d) make such changes in the scheme as the Committee deems fit from time to time. The Licensing Committee shall be empowered to frame rules and regulations from time to time inter-alia providing for the conditions to be compiled with by an applicant before he would be entitled to quotas. It shall also have the right to withhold or cancel quotas and reject applications for quotas without assigning any reasons.
 - 11. The address of the Cotton Textiles Export Promotion Council is as follows:-

"ENGINEERING CENTRE"
5th Floor, 9, Mathew Road, Bombay-4.
9, Mathew Road,
BOMBAY-4.

- विषम.--लाइसेंग वर्ष 1974 के दौरान पोणाकों श्रीर तैयार वस्तुशों सहित भारतीय मिल निर्मित सूती वस्त्रों का डेनमार्क तथा श्रायरलैंग्ड (श्राहरिण गणराज्य) की निर्मात के लिए लाइसेंग देने में सम्बन्धित योजना ।
- सं० 2 हैं ब्रिंगिल (पी०एन०) /74 यह योजना लाइमेंस वर्ष 1 जनवरी, 1974 मे 31 दिसम्बर 1974 के दौरान भारत में उत्तमार्क तथा धायरलैण्ड को सभी किस्म के मिल निर्मित सुती वस्त्रों, तैयार वर स्त्रीर तैयार पोणाकों के निर्मात से सम्बन्ध रखती है।
- 2. लाइसेंस देने के वि र से पोतलदान की श्रवधि को 1 जनवरी, 1974 से 30 जून, 1974, तथा 1 जुलाई, 1974 से 31 दिसम्बर, 1974 तक छः छः माह की दो श्रवधियों में बांटा जाएगा ।
- 3. इस योजना के श्रन्तर्गत लाइसेंस संयुवत मुख्य नियंत्रक श्रायात निर्यात, के कार्यालय बम्बई द्वारा ई ई सी—ग्रास्ट्रिया वस्त्र लाइसेंस सलाहकार समिति की सिफारिण पर सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई द्वारा जारी किए गए कोटा प्रमाणपत्र के श्राधार पर जारी किए जाएंगे।
- 4 निर्यातों श्रीप कोटें/लाडसेंसों को जारी करने के लिए सूती वस्त्रों को निम्नलिखित भागों में विभक्त किया गया है:---
 - वर्ग 1.—स्ती वस्त्र, भूरे या विरंजित रेशमी सा बनाया हुआ था बिना विरंजित रेशमी सा बना हुआ था बिना विरंजित रेशमी सा बना हुआ। वर्ग 1 में नीचे लिखी थे णियों के अन्तर्गत वर्गीकृत मदें आसी हैं: बी०, बी०1, बी2 बी3, बी4, बी5, बी6, बी7, बी8, सी तथा सी1। वर्ग 2 में नीचे लिखी श्रेणियों के अन्तर्गत आन वाली मदे आती हैं:—
 - **बर्ग** 2.—-प्रन्य सूती वस्त्र, तैयार शामग्री श्रीए सूनी की विविध सामग्री : सी 2. सी -3, सी -4 सी -5, सी -6, सी -7, डी डी -1, डी -2, डी -3, डी -4; डी - हि -1, ई -2, ई -3, ई -4, ई 5, ई -6, ई -7, ई -8, ई -9, ई -10, ई -11, एफ, एफ -1, एफ -2, एफ -3, तथा एफ -4।

उपर्युवत श्रेणियों के भ्रन्तर्गत स्नाने वाली भवों का विवरण वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् के यहां मानकी-कत वर्गीकरण, के रूप में श्रीर उनके श्रन्तर्गत स्नान वाली मदों के रूप में उपलब्ध है ।

- 5. करार के श्रनुसार डेनमार्क श्रौर श्रायरलैण्ड में सूती वस्त्रों के श्रायात की श्रनुमति केवल सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, वस्त्रई द्वारा जारी किए गए ग्रीन सार्टीफिकेट के प्रस्तुतीकरण पर ही सम्बद्ध समर्थ प्राधिकारियों द्वारा दी जाएगी, जिसके श्राधार पर डेनिश श्रौर श्राइरिश प्राधिकारी श्रायात लाइसेंस जारी करेंगे।
 - लाइसेंस भारत के किसी भी पत्तन के पोतलदान के लिए बैध होंगे।
- 7. ई० ई०सी० प्रास्ट्रिया वस्त्र लाइसेंस सलाहकार समिति की लिखित रूप में स्पाट स्वीकृति के बिना लाइसेंस और कोर्टे हस्तांतरणीय नहीं होंगे।
- कोटा जारी करने के लिए सूतीबस्त्र निर्यात संबर्धन परिषद द्वारा प्रति टन 10 ६०
 के हिसाब से एक प्रदेय णुल्क बसूल किया जाएगा और यह न्यूततम 5 रुपये के प्रधीन होगा।

- भभी कोटाधारी जिनको अलग अलग लाइसेंस जारी किए गए हैं, उसके लिए उन्हें
 पोतलदान का विवरण देने हुए सुतीवस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद को एक मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी पड़ेगी। ये व्यौरे परिषद के पास अनुवर्ती मास की 10 तारीख तक पहुंच जाने चाहिएं।
- 10. ई० ई०सी० श्रास्ट्रिया वस्त्र मलाहकार समिति के यं कार्य होंगे (क) सम्पूर्ण योजना का पर्यवेक्षण करना. (ख) समय समय पर कार्य पालन की निगरानी रखना, (ग) योजना के परिचालन से सम्बन्धित उत्पन्न विभिन्न मामलों का विवेचन करना और निर्णय देना तथा (घ) योजना में समय समय पर ऐसे परिवर्तन करना जिसे समिति उपयुक्त समझें। कीटा प्राप्त करने के लिए पात्र बनने से पहतें की शतों का श्रावेदक से पालन कराने के साथ-साथ लाइसेंस समिति समय-समय पर नियम तथा विनियम बनाव के लिए श्रिष्ठकृत है। उसे यह भी श्रिष्ठकार होगा कि वह कीटा को रोक जै या उसे रह कर दे और बिना किसी कारण के समनदेशित किए ही कोटा के लिए दिए गए आयेदन पत्र को रह करदे।
 - 11. सूती वस्त्र निर्यात संदर्भन परिषद् का पता निम्निलिखित है:—
 ''इंजीनियरिंग सेन्टर'',
 5वी मंजिल.
 9, मैथ्यू रोड,
 बम्बई-4.
- Subject.—Scheme for the licensing of Indian millmade cotton textiles including garments and made-ups for export to WEST GERMANY during the licensing year 1974.
- No. 3-ETC(PN)/74.—The Scheme relates to the export of all varieties of mill-made cotton fabrics, made-up items and readymade garments made out of mill-made fabrics from India to WEST GERMANY during the licensing year 1st January, 1974 to 31st December, 1974.
- 2. For purpose of licensing the shipment period will be divided into two sixmonthly periods, 1st January, 1974 to 30th June, 1974 and 1st July, 1974 to 31st December, 1974.
- 3. Licences under the Scheme shall be Issued by the Office of the Jt. Chief Controller of Imports & Exports, Bombay, on the basis of quota certificates issued by The Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay, on the recommendations of the EEC-Austria Textiles Licensing Advisory Committee.
- 4. For the purpose of exports and issuance of quotas/licences, cotton textiles have been divided into the following two groups:—
 - Group I:—Cotton fabrics, grey or bleached mercerised or not:

Group I covers items classified under categories B, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, C and C1.

Group II:—Other cotton fabrics, made-up articles and miscellaneous articles of cotton:

Group II covers items falling under categories C2, C3, C4, C5, C6, C7, D, D1, D2, D3, D4, E, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, F, F1, F2, F3 and F4.

Details of the items falling under the above categories are available with the Texprocil in the form of standardised categories and items falling under the same.

- 5. According to the agreement, imports of cotton textiles into West Germany will be admitted by the competent West German Authorities only on presentation of the Green Certificates issued by the Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay, on the basis of which West German Authorities would issue import licence.
 - 6. Licences shall be valid for shipment from any port in India.

- 7. Licences and quotas shall not be transferable without the express consent in writing of the E.E.C. and Austria Textiles Licensing Advisory Committee.
- 8. A non-refundable charge of Rs. 10 per ton will be levied by the Cotton Textiles Export Promotion Council for the issue of quotas, subject to a minimum of Rs. 5.
- 9. All quota holders shall have to submit a monthly report to The Cotton Textiles Export Promotion Council, glving details of the shipment against individual licences issued to them. These statements should reach the Council by the 10th of the subsequent month.
- 10. The E.E.C.-Austria Textiles Licensing Advisory Committee shall (a) supervise the entire scheme; (b) keep a watch over the performance from time to time; (c) interpret and give decisions on various matters arising out of the operation of the scheme; and (d) make such changes in the scheme as the Committee deems fit from time to time. The Licensing Committee shall be empowered to frame rules and regulations from time to time, inter-alla providing for the conditions to be compiled with by an applicant before he would be entitled to quotas. It shall also have the right to withhold or cancel quotas and reject applications for quotas without assigning any reasons.
 - 11. The address of The Cotton Textiles Export Promotion Council is as follows:—

"ENGINEERING CENTRE" 5th Floor, 9, Mathew Road, BOMBAY-4.

S. G. BOSE MULLICK.

Chief Controller of Imports & Exports.

विश्वयः -- लाइसेंस वर्ष 1974 के दौरान पश्चिमी अमेनी को पहनावे तथा तैयार माल सहित भारतीय मिल निर्मित सूती वस्त्रों के निर्यात के लिए लाइसेंस देने से सम्बन्धित योजना।

स० 3 ई० टी० सी० (पी० एन०)/ए४.—यह योजना पहली जनवरी, 1974 से 31 दिसम्बर, 74 तक के लाइसेंस वर्ष के दौरान परिश्वमी जर्मनी को भारत से सभी प्रकार के मिल निर्मित मुती वस्त्रों, तैयार महों और मिल निर्मित वस्त्रों से बने हुए तैयार पहनावों के निर्मात से सम्बन्ध रखनी है।

- 2. लाइसेंन प्रदान किए जाने के विचार से पोतलदान की ग्रवधि को पहली जनवरी 1974 से 30 जून, 1974 तक भीर पहली जुलाई, 1974 से 31 दिसम्बर, 1974 तक की दो छहमाहियों में बांटा जाएगा ।
- 3. इ.म. योजना के ग्रन्तर्गेत लाइसेंस ई०ई०सी०-श्रास्ट्रीया वस्त्र लाइसेंस परामर्श दायी सिमिति की निफारिश पर सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, बस्बई द्वारा जारी किए गए कोटा प्रमाण के ग्राधार पर संयुक्त गुरुय नियंत्रक, ग्रायात निर्यात के कार्यालय, बम्बई द्वारा जारी किया जाएगा ।
 - 4. निर्यातों ग्रीर कोटा लाइसेंसों को जारी करने के लिए सूती वस्त्रों को निम्नलिखित दो वर्गों में विभक्त किया गया है :---
 - वर्ग 1.—सूती वस्त्र, भूरे या विरंजित रेशमी सा बनाया हुआ। या बिना विरंजित रेशमी मा बना हुआ। वर्ग 1 में नीचे लिखी श्रेणियों के अन्तर्गात वर्गीकृत मदें अप्रती हैं:
 - बी, बी 1, बी 2, बी 3, बी 4, बी 5, बी 6, बी 7, बी 8, सी तथा सी-।।

वर्ग 2.—अन्य सूती वस्त्र, तैयार सामग्री और मूती की विविध सामग्री।
वर्ग 2 में नीचे लिखी श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाली महें आती है:

सी 2, सी 3, सी 4, सी 5, सी 6, सी 7, डी, डी 1, डी 2, डी 3, डी 4, ई, ई 1, ई 2, ई 3, ई 4, ई 5, ई 6, ई 7, ई 8, ई 9, ई 10, ई 1 1, एफ, एफ 1; एफ 2 एफ 3, तथा एफ 4 ।

उपर्युक्त श्रेणियों के अन्तर्गत भाने वाली सदों का विवरण वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद के यहां मानकी-कृत वर्गीकरण के रूप में और उनके अन्तर्गत आने वाकी मदों के रूप में उपलब्ध है।

- 5. करार के अनुमार पिण्यमी जर्मनी में सूतीवस्त्रों के आयात की अनुमति केवल सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई द्वारा जारी किए गए प्रीन सार्टीफिकेट के प्रस्तृतीकरण पर ही सम्बद्ध समर्थ पश्चिमी जर्मन प्राधिकारियों द्वारा दी जाएगी, जिसके आधार पर पश्चिमी जर्मन प्राधिकारी आयात लाइसेंस जारी करेंगे।
 - 6. लाइसेंस भारत के किसी भी पत्तन से पोतलदान के लिए वैय होंगे।
- 7. ई० ई० सी० ग्रास्ट्रिया वस्त्र लाइसेंस सलाहकार शामित की लिखित रूप में स्पण्ट स्वीकृति के बिना लाइसेंस भीर कोटे हस्तांतरणीय नहीं होंगे ।
- 8. कोटा जारी करने के लिए सूतीवस्त्र निर्यात संवर्धन परिषय द्वारा प्रति टन 10 रुपये के हिसाग से एक प्रदेय णुल्क वसूल किया जाएगा और यह न्यूनतम 5 स्पये के प्रधीन होगा।
- 9. सभी कोटाधारी जिन को ग्रालग प्रालग लाइसेंस जारी किए गए हैं, उसके लिए उन्हें पोतलटान का विवरण देते हुए सूतीवस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद को एक मासिक रिपोर्ट प्रस्तृत करनी पड़ेंगी। ये ब्योरे परिषद के पास ग्रनुवर्ती मास की 10 तारीख, तक पहुंच जाने चाहिए।
- 10. ई० ई० सी० ग्रास्ट्रिया वस्त्र सलाहकार सिमिति के ये कार्य होंगे (क) सम्पूर्ण योजना का प्रयंवेक्षण करना, (ख)समय-समय पर कार्य पालन की निगरानी रखना (ग) योजना के परिचालन से सम्बन्धित उत्पन्न विभिन्न मामलों का विवेचन करना ग्रीर निर्णय देना तथा (घ) योजना में समय समय पर ऐसे परिवर्तन करना जिसे सिमिति उपयुक्त समझे। कोटा प्राप्त करने के लिए पाल बनने से पहले की गर्तों का श्रावेदक से पालन कराने के साथ-साथ लाइसेंस सिमिति समय समय पर नियम तथा विनियम बनाने के लिए श्रिष्टिहत है। उसे यह भी श्रिष्ठकार होगा कि वह कोटा को रोक ले या उसे रह कर दे श्रीर बिना किसी कारण के समनुदेशित किए ही कोटा के लिए दिए गए श्रावेदन पत्र को रह करदे।
 - 11. सूती वस्त्र निर्यात संबर्धन परिषद् का पता निम्निसिखित है '--"इंजीनियरिंग सेन्टर",
 5वीं मंजिल,
 9, मैंश्यू रोड,
 वमवर्ष-4 ।

्रस० जी० बोस महिलक, मुख्य नियंत्रक, ग्रायात नियति ।